ए-45011/03/2024-समन्वय .II

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

***

नई दिल्ली, 31 मई, 2024

कार्यालय ज्ञापन

अधोहस्ताक्षरी को अप्रैल, 2024 के लिए आर्थिक कार्य विभाग के संबंध में महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों पर मासिक सारांश का अवर्गीकृत भाग इसके साथ परिचालित करने का निदेश हुआ है।

सु. सामंत

(सुश्रुत सामंत)
उप सचिव, भारत सरकार
दूरभाष सं. 2309-5244

सेवा में

1. केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. उपाध्यक्ष, नीति आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली।
3. मंत्रिमंडल सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
4. भारत के राष्ट्रपति के सचिव, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
5. भारत के उपराष्ट्रपति के सचिव, 6, मौलाना आज़ाद रोड, नई दिल्ली।
6. प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, पीएमओ, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली।
7. अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, नई दिल्ली।
8. नीति आयोग के सभी सदस्य, योजना भवन, नई दिल्ली।
9. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव, नई दिल्ली।
10. वित्त राज्य मंत्री के निजी सचिव, वित्त सचिव के निजी सचिव, सचिव (ईए) के निजी सचिव, सचिव (राजस्व) के निजी सचिव, सचिव (व्यय) के निजी सचिव, सचिव (दीपम) के निजी सचिव।
11. श्री वी. अनंत नागेश्वरन, मुख्य आर्थिक सलाहकार, आर्थिक कार्य विभाग।
12. अपर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
13. श्री मनोज सहाय, एएस एंड एफए (वित्त)।
14. सुश्री अपर्णा भाटिया, सलाहकार (प्रशासन/समन्वय/सी एंड सी)
15. सुश्री मनीषा सिन्हा, अपर सचिव (ओएमआई/क्रिप्टो संपत्ति और फंड बैंक)
16. आर्थिक कार्य विभाग के सभी प्रभाग प्रमुख। संयुक्त सचिव (आईपीपी/संयुक्त सचिव (आईएसडी)/संयुक्त सचिव (इन्वेस्टमेंट)/संयुक्त सचिव (बजट) संयुक्त सचिव (एफएम)/सभी सलाहकार/सीएएए
17. श्री राजेश मल्होत्रा, महानिदेशक (एम एंड सी), वित्त मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
18. गार्ड फाइल – 2024

ए-45011/03/2024-समन्वय.II

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

***

विषय: अप्रैल, 2024 हेतु आर्थिक कार्य विभाग (आ.का.वि.) से संबंधित महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों पर मासिक सारांश।

1. माह के दौरान लिए गए महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय और प्रमुख उपलब्धियाँ:

वृहद आर्थिक सिंहावलोकन:

मंदी की आशंका कम होने से वैश्विक आर्थिक विकास में क्रमिक रूप से संवर्धन हुआ। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने अपनी वर्ल्ड इकोनोमिक आउटलुक (डब्ल्यूईओ) अप्रैल 2024 रिपोर्ट में अनुमान लगाया है कि वैश्विक वृद्धि 2024 और 2025 में 3.2 प्रतिशत पर स्थिर रहेगी, जो जनवरी 2024 के अपडेट में 3.1 प्रतिशत से कुछ अधिक है। प्रमुख संकेतकों ने वैश्विक आर्थिक गतिविधि में तेजी को दर्शाया। वैश्विक विनिर्माण पीएमआई अप्रैल 2024 में सभी आयामों में विस्तार के साथ 50 अंक से ऊपर रहा।

वैश्विक वृद्धि मे उछाल के साथ-साथ विकास की अलग-अलग प्रवृत्तियां भी हैं। जबकि अधिकांश प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं ने सुदृढ बढ़त दिखाई, कई अन्य अर्थव्यवस्थाएँ पीछे रही हैं। आईएमएफ ने मुख्य रूप से उधार की उच्च लागत, राजकोषीय सहायता हटना, कमजोर उत्पादकता वृद्धि और भू-आर्थिक विखंडन में वृद्धि को विस्तार की धीमी गति हेतु जिम्मेदार ठहराया है।

भविष्य-उन्मुख संकेतकों ने मनोभावों में सुधार को दर्शाया। मार्च 2024 में भू-राजनीतिक जोखिम संकेतक में गिरावट आई, जो जोखिम धारणाओं में नरमी का संकेत है। पश्चिम एशिया में हाल के बढ़े सघर्ष को छोड़कर, भू-राजनीतिक तनावों के कारण अस्थिरता और अनिश्चितता कम होती दिख रही है। यह वैश्विक विकास के लिए भी एक सकारात्मक पहलू है। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर दबाव भी कम हुआ, जिससे संभार तंत्र संबंधी चुनौतियाँ कम हुईं।

अप्रैल 2024 में वैश्विक उत्पाद की कीमतों में वृद्धि जारी रही, जो ऊर्जा और गैर-ऊर्जा दोनों उत्पादों द्वारा संचालित थी। दिसंबर 2023 से कच्चे तेल की कीमतों में मजबूती आई है, जो आंशिक रूप से पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और ओपेक+ देशों द्वारा 2024 के मध्य तक आपूर्ति बाधाओं को बनाए रखने के निर्णय से प्रेरित है।

भारतीय अर्थव्यवस्था ने सभी क्षेत्रों में व्यापक आधार पर वृद्धि के साथ मजबूत आर्थिक प्रदर्शन जारी रखा। अप्रैल के डब्ल्यूईओ ने घरेलू मांग में निरंतर मजबूती और बढ़ती कामकाजी आयु वाली आबादी के आकलन के आधार पर 2024-25 में भारत की वृद्धि दर 6.8 प्रतिशत और 2025-26 में 6.5 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है।

नवीनतम उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण के अनुसार, सामान्य आर्थिक स्थिति और रोजगार की संभावनाओं पर परिवारों की मनोदशाओं में वर्तमान अवधि के साथ-साथ आगामी वर्ष के लिए भी उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया गया है। निरंतर लाभप्रदता और ग्रामीण मांग में तेजी के कारण विनिर्माण क्षेत्र में भी अपनी गति बने रहने की उम्मीद है। फरवरी 2024 के लिए औद्योगिक उत्पादन के नवीनतम सूचकांक (आईआईपी) के अनुसार, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं 12.3 प्रतिशत की प्रभावशाली वृद्धि दर दर्ज करते हुए एक बेहतरीन प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभरी हैं।

2. महत्वपूर्ण घटनाक्रम :

(i) माननीय वित्त मंत्री ने आईएमएफ में भारत के गवर्नर के रूप में आईएमएफ में **लीख्टेनश्टाइन की रियासत की सदस्यता को मंजूरी देने** के लिए मतपत्र पर इसके पक्ष में मतदान किया।

(ii) भारत ने आईएमएफ के प्रबंध निदेशक के पत्र के जवाब में **एनएबी (उधार लेने की नई व्यवस्था) के तहत ऋण व्यवस्था को वापस लेने पर** (आईएमएफ में कार्यकारी निदेशक (भारत) के माध्यम से) सहमति व्यक्त की।

(iii) भारत सरकार ने **अफ्रीकी विकास बैंक (एएफडीबी)** की मौजूदा 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर से 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक आईएनआर-मूल्यवर्गित **अपतटीय उधार** की सीमा के विस्तार को मंजूरी दी।

(iv) अप्रैल, 2024 के दौरान **जी20 ब्राजील प्रेसीडेंसी के तहत निम्नलिखित वित्त ट्रैक बैठकें** आयोजित की गईं:

क) **जी20 सतत वित्त कार्य समूह की दूसरी बैठक (एसएफडब्ल्यूजी)** 1-2 अप्रैल, 2024 को ब्रासीलिया में आयोजित की गई थी। बैठक के बाद 3 अप्रैल, 2024 को 'शहरों में एसडीजी वित्त' और 'स्थानीय मुद्रा में जलवायु वित्त' पर 2 सह कार्यक्रम हुए।

ख) 17-18 अप्रैल, 2024 को वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक-अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (डब्ल्यूबी-आईएमएफ) स्प्रिंग बैठकों के मौके पर **दूसरी जी20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों (एफएमसीबीजी) की बैठक** आयोजित की गई थी। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व आरबीआई के गवर्नर और सचिव, आर्थिक कार्य ने किया था। बैठक दो विषयगत सत्रों में आयोजित की गई थी। पहला सत्र न्यायोचित परिवर्तन और जलवायु लक्ष्यों के लिए वित्त की पुनर्कल्पना पर था। चर्चा जलवायु संकट से निपटने में विकासशील देशों के परिप्रेक्ष्य और चुनौतियों से जुड़े मुद्दों पर केंद्रित थी। दूसरा सत्र 21वीं सदी के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय ढांचे पर था। चर्चा मुख्य मुद्दों पर केंद्रित थी जो बहुपक्षीय विकास बैंकों (एमडीबी) के सुधारों के लिए जी 20 रोडमैप के निर्माण का मार्गदर्शन करेंगे ताकि एमडीबी को बेहतर, व्यापक और अधिक प्रभावी बनाया जा सके।

(v) सचिव, आर्थिक कार्य के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने 15 से 19 अप्रैल, **2024 तक वाशिंगटन डीसी में आईएमएफ और विश्व बैंक की 2024 स्प्रिंग मीटिंग** में भाग लिया।

क) सचिव, आर्थिक कार्य ने 17 अप्रैल, 2024 को वाशिंगटन डीसी में आयोजित एफएसबी संचालन समिति की बैठक में भी भाग लिया। बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ मार्जिनिंग प्रक्रियाओं और गैर-बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थों के डेटा मुद्दों पर चर्चा की गई।

ख) स्प्रिंग मीटिंग के अवसर पर, सचिव, आर्थिक कार्य ने अमेरिका, ब्रिटेन, सऊदी अरब, जापान, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के समकक्षों के साथ-साथ वित्तीय स्थिरता बोर्ड के अध्यक्ष, आईएमएफ के प्रथम उप प्रबंध निदेशक, आईएफसी के उपाध्यक्ष, एमआईजीए के

उपाध्यक्ष, लोगों और प्लेनेट के लिए पेरिस संधि के विशेष प्रतिनिधि आदि के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी कीं।

ग) **आईडीए21 की दूसरी पुनःपूर्ति बैठक** 21-22 अप्रैल, 2024 को वाशिंगटन डीसी में आयोजित की गई थी।

(vi) आधिकारिक स्तर पर निम्नलिखित महत्वपूर्ण बैठकें आयोजित की गईं/उनमें भाग लिया गया:

क. भारत के लिए **वित्तीय क्षेत्र आकलन कार्यक्रम (एफएसएपी)** के लिए आईएमएफ और विश्व बैंक की संयुक्त टीम की बैठक, जिसकी अध्यक्षता आईएमएफ और विश्व बैंक द्वारा संयुक्त रूप से 5 वर्षों में एक बार आयोजित की जाती है, मार्च में आयोजित की गई थी और समापन बैठक 1 अप्रैल, 2024 को आयोजित की गई थी।

ख. विश्व बैंक वित्तपोषण के तहत परियोजनाओं की **त्रिपक्षीय पोर्टफोलियो और पाइपलाइन समीक्षा बैठक** 03 से 5 अप्रैल, 2024 को आयोजित की गई।

ग. **एआईआईबी निदेशक मंडल** की बैठक आभासी रूप से दिनांक 17 अप्रैल, 2024 को हुई।

घ. आईएफएडी की 141वीं कार्यकारी बोर्ड की बैठक 22-24 अप्रैल को रोम, इटली में आयोजित की गई, जिसमें बोर्ड ने भारत के एक परियोजना प्रस्ताव पर विचार किया जिसका शीर्षक था – **जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार परियोजना (जेएंडकेसीआईपी)** जिसके लिए 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया जाना था। यह जम्मू और कश्मीर में आईएफएडी द्वारा स्वीकृत प्रथम परियोजना है।

ङ. **भारत–उरुग्वे निवेश वार्ता** 25 अप्रैल, 2024 को आयोजित की गई थी।

च. **एनडीबी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स** की 9वीं वार्षिक बैठक वस्तुतः 26 अप्रैल, 2024 को आयोजित की गई थी।

छ. वित्तीय स्थिरता बोर्ड के तहत, **क्षेत्रीय सलाहकार समूह (आरसीजी) एशिया की बैठक** 28-30 अप्रैल, 2024 को श्रीलंका में आयोजित की गई थी। एजेंडा मदों में वित्त में एआई का उपयोग, जलवायु जोखिम मूल्यांकन, सीमा पार भुगतान मुद्दे, वैश्विक और क्षेत्रीय जोखिम आदि शामिल हैं।

(vii) **अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के कार्यकारी बोर्ड** में निम्नलिखित महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई:

क) ऋण पुनर्संरचना करने वाले देशों को सहायता प्रदान करने के लिए आईएमएफ की क्षमता को प्रोत्साहित करने के लिए नीतिगत सुधार विकल्प;

ख) पाकिस्तान – स्टैंड-बाई व्यवस्था के तहत दूसरी समीक्षा;

ग) कोष की पारदर्शिता नीति और ओपन आर्काइव्स पॉलिसी की समीक्षा; और

(viii) आईईएस अधिकारी प्रशिक्षु 2024, 17 अधिकारियों के एक बैच ने 18 अप्रैल, 2024 को कार्यभार ग्रहण किया है और उन्होंने अपना परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण आरंभ कर दिया है।

3. न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन

सूचना प्रस्तुत करने में आईसीटी के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

4. एसीसी निर्देशों/आदेशों का अनुपालन न करना: शून्य

5. माह के दौरान स्वीकृत एफडीआई प्रस्तावों का ब्यौरा और विभाग में अनुमोदन हेतु प्रतीक्षित एफडीआई प्रस्तावों की स्थिति:

स्वीकृत प्रस्तावों की संख्या	:	01
विभाग में अनुमोदन की प्रतीक्षा	:	11